

तारीख हुक्म	<p>राजस्व अपील संख्या 29/2016</p> <p>ताराराम वगैरह बनाम नारायण वगैरह</p> <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

19/12/2022 अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अन्तरिम आदेश दिनांक 17.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी से संबंधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन/लंबित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियों में न्यायहित को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण को इस स्तर पर लंबित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के इस मत पर अपनी सहमति जाहिर की गई।

प्रकरण में अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 05 से 08 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मोजा बागरा तहसील व जिला जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 893/3098 रकबा 0.7000 हैक्टेर किस्म साही सोयम के संबंध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2015 को वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात पत्रावली वास्त तलबी में नियत थी। इस दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प बागरा में जैर अपील आदेश के जरिये पूर्व में जारी आदेश दिनांक 10.07.2015 को खारिज कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारों का आपस में बंटवाडा नहीं हुआ है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अपने हिस्से का बेचान रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 को कर दिया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 अजनबी क्रेता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों के नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 05 से 08 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मोजा बागरा तहसील व जिला जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 893/3098 रकबा 0.7000 हैक्टेर किस्म साही सोयम के संबंध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2015 को वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 29/2016</p> <p style="text-align: center;">ताराराम वगैरह बनाम नारायण वगैरह</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प बागरा मे जैर अपील आदेश के जरिये पूर्व मे जारी आदेश दिनांक 10.07.2015 को खारिज कर दिया गया। हस्तगत प्रकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमे मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य है, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है—

आदेश 39 नियम 3

3. Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party-

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

- 1. a copy of the affidavit filed in support of the application.*
- 2. a copy of the plaint and*
- 3. copies of doucments on which the applicant relies, and*

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 29/2016</p> <p style="text-align: center;">ताराराम वगैरह बनाम नारायण वगैरह</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहाँ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणों को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील व्यादेश एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत शेष रेस्पोंडेन्टगण की तलबी पूर्ण नहीं हुई। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामलो को न्यायालय द्वारा 30 दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणों को अभिलेखित करना चाहिए।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील जैर अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है प्रकरण से संबंधित मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मे निर्णीत होगा। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रकरण के इस स्तर पर किसी प्रकार का तर्क दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र का लगभग 07 वर्षों से अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है एवं प्रार्थना पत्र लंबित होने से पक्षकारों को न्याय प्राप्त होने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। प्रकरण मे किसी भी पक्ष की ओर से हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के संबध माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2015 बउनवान ताराराम बनाम नारायण मे पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तदनुसार उपखंड अधिकारी सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबंधित विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2015 बउनवान ताराराम बनाम नारायण के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 29/2016 ताराराम वगैरह बनाम नारायण वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

१
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली